मरु कमल दर्पण

मासिक

वर्ष : 16 अंक : 6 • जून, 2026 • प्रकाशन तिथि : 25 जून, 2026 • मूल्य : 20 रु. प्रति • 200 रु. वार्षिक • पृष्ठ : 28

12 साल विश्वास के, विकास के एवं जनकल्याण के

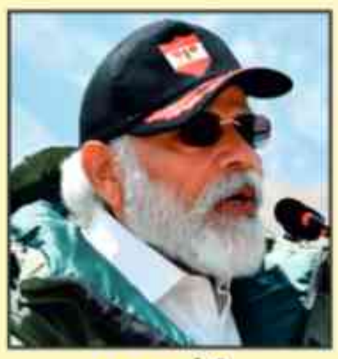

प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी

केन्द्रीय गृह मंत्री
श्री अमित शाह

केन्द्रीय रक्षा मंत्री
श्री राजनाथ सिंह

सत्ता और संगठन

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
श्री मदन राठौड़

मुख्यमंत्री
श्री भजनलाल शर्मा

भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन)
श्री अजेय कुमार

केन्द्रीय मंत्री

श्री अर्जुनराम मेघवाल

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

श्री भूपेन्द्र यादव

श्री भागीरथ चौधरी

जो धर्म, संस्कृति, विरासत और विकास चारों को साथ लेकर चले,
वही सच्चा जननेता, विजय सत्य-सनातन की

सोमनाथ मंदिर (गुजरात)

श्रीराम मंदिर अयोध्या (उत्तर प्रदेश)

भोजशाला (मध्य प्रदेश)

12 साल में मोदी सरकार ने क्या किया

- सोमनाथ मंदिर के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की पूजा-अर्चना।
- 721 साल बाद धार की भोजशाला में हुई पूजा।
- 500 साल बाद मिला राम मंदिर अयोध्या।
- 500 साल बाद पावागढ़ के महाकाली मंदिर में फहराई धर्म ध्वजा।
- 31 साल बाद ज्ञानवापी में मिला फिर पूजा का अधिकार।

मोदी न होते तो क्या ये देखने को मिलता ?

मरु कमल दर्पण
(मासिक)

अंक–06 (वर्ष–16)
प्रेषण तिथि
29 जून 2026

मार्गदर्शक
मदन राठौड़
अजेय कुमार

सम्पादक
डॉ. सतीश पूनियां

सह सम्पादक
प्रोफेसर बीरुसिंह राठौड़

सम्पादक मण्डल
सुनील कोठारी
चम्पालाल रामावत

कार्यालय प्रबन्धन
त्रिलोक शर्मा

वार्षिक शुल्क
दो सौ रुपए
आजीवन शुल्क
एक हजार रुपए

प्रबन्धकीय कार्यालय
सी–51, सरदार पटेल मार्ग
सी–स्कीम, जयपुर–302001
मो. 9314602641
E-mail : marukamaldarpan@yahoo.in

विषय सूची

- अपनी बात.... 04
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल 05
- सोमनाथ और भारत का अजेय जज्बा : नरेन्द्र मोदी 06–07
- देश को कांग्रेस के कुचक्र से बचाया 08
- श्री अजेय कुमार बने राजस्थान के भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) 09
- मोदी सरकार– 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के 10
- मोदी के आह्वान का विरोध व आलोचनाएं केवल राजनीतिक.... 11–12
- पश्चिम बंगाल : परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण : राजनाथ सिंह 13
- घुसपैठियों पर कसी जाएगी नकेल : अमित शाह 14
- आत्मनिर्भर भारत : स्वदेशी चेतना का पुनर्जागरण : भजनलाल शर्मा 15–16
- राजस्थान में भजनलाल सरकार का 02 वर्षीय रिपोर्ट कार्ड : शहजाद 17
- तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनाक्रोश से भाजपा भी अचंभित 18
- राजस्थान के जल भविष्य की नई धारा : राजेन्द्र राठौड़ 19–20
- परम्परा, पर्यावरण और जन भागीदारी का संगम 21–22
- महाराणा प्रताप के अदम्य साहस की ऐतिहासिक गाथा 23–24
- मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में समग्र विकास का नया अध्याय 25–26

अपनी बात

प्रगति की नई रफ्तार : विकसित राजस्थान का संकल्प धीरे–धीरे होने लगा साकार

प्रिय बन्धुवर,

सप्रेम नमस्कार।

राजस्थान दिवस पर जारी आंकड़े प्रदेश की विकास यात्रा का ठोस दस्तावेज है। यह आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार की ओर से अल्प समय में ही पकड़ी प्रगति की नई रफ्तार से विकसित राजस्थान का संकल्प साकार हो रहा है। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही "विकसित राजस्थान 2047" के लक्ष्य को केन्द्र में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया। यही कारण है कि अनेक योजनाओं में राजस्थान देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पहुंचा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसी जारी होना इस बात का प्रमाण है कि किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का अभूतपूर्व कार्य हुआ। पोषण–कुपोषण योजना के कंपोनेंट–ए एवं सी के सफल क्रियान्वयन ने सामाजिक क्षेत्र में भी सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। कृषि क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने तकनीक और पादर्शिता को प्राथमिकता दी है। कृषि विभाग की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, किसानों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण में तेजी और पारदर्शिता जैसे कदम पूर्ववर्ती सरकार की धीमी कार्यप्रणाली से स्पष्ट बदलाव को दर्शाते है। 'पर ड्रॉप– मोर क्रॉप' योजना के तहत 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रों इरिगेशन सिस्टम की स्थापना जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और किसानों की आय बढ़ाने का भी मजबूत माध्यम बना है। पशुपालन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण है कि राज्य की डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफलता पाई है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले 6 वर्षों (2018–2023) की तुलना में वर्तमान सरकार के 25 माह (2024–2026) के कार्यकाल में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान सरकार ने मात्र 25 महीनों में 3.41 लाख को प्रशिक्षित किया गया।

कृषि क्षेत्र में पहले 29,430 फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) बनाए गए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 35,368 हो चुकी है। ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले 13,160 सोलर पंप स्थापित किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 16,864 हो गई है। "पर ड्रॉप–मोर क्रॉप" जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन स्थापित कर जल प्रबंधन को नई दिशा दी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले जहां केवल 1,478 गांव इससे जुड़े थे, वहीं अब यह आंकड़ा 41,037 गांवों तक पहुंच गया है। पहले 1,104 गांव सड़कों से जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1,717 हो गई है। मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवसों में तो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ढाणियों के विद्युतीकरण में पहले 3,952 कार्य हुए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 8,261 हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत जहां पहले 2,92,507 घरों को नल कनेक्शन मिले थे, वहीं अब यह बढ़कर 3,14,530 हो चुका है। प्रशासनिक सुधारों से जहां पहले केवल 986 पट्टों का वितरण हुआ था, वहीं वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 88,724 तक पहुंचा दिया है। कृषि कनेक्शन के क्षेत्र में पहले – 21,136 कनेक्शन दिए गए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 41,820 हो गई है। उच्च शिक्षा में जहां पहले केवल 5 महाविद्यालय स्थापित हुए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21 हो गई है। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपखंड कार्यालय भवन निर्माण में पहले मात्र 57 भवन बने थे,

अब यह संख्या बढ़कर 185 हो गई है। सड़क निर्माण में पहले 10.36 हजार किमी, अब 11.31 हजार किमी निर्माण हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले जहां 10 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 18 हो गई है। स्कूल अपग्रेडेशन में अब 403 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आंकड़ों का यह अन्तर शासन की कार्यशैली का परिणाम है। वर्तमान सरकार ने ''गुड गवर्नेस'' और ''डिलीवरी'' को प्राथमिकता दी है। योजनाएं कागजों से बाहर निकलकर खेतों और गांवों तक पहुंच रही हैं

केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन भी इस प्रगति का एक बड़ा कारण है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में राजस्थान की अग्रणी भूमिका यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से विकास को नई गति मिलती है। विकास अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। अल्प समय में ही अनेक क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि यह संकेत देती है कि ''विकसित राजस्थान 2047'' का सपना साकार हो रहा है। राजस्थान आज अपने अतीत की विरासत पर गर्व कर रहा है और अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

(मदन राठौड़)
प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा राजस्थान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल : राजस्थान ने रचा इतिहास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने सफल 25 वर्ष पूरे कर लिए है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बनाई है। प्रदेश में अब तक 75868 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, जिसके लिए राजस्थान को सर्वाधिक सड़क लंबाई पूरी करने की श्रेणी में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

योजना के चौथे चरण में राजस्थान को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने इस चरण में देशभर के लिए स्वीकृत 4795 सड़कों में से अकेले राजस्थान की 1216 सड़कें आवंटित की हैं। सड़कों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

इसके तहत 3219 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी, जिसके लिए 2000 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। मुख्य लक्ष्य 2011 की जनगणना के आधार पर सड़क सम्पर्क से वंचित मरूस्थलीय, जनजातीय और आकांक्षी जिलों की बस्तियों, को ऑल वेदर (हर मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ना हैं)

22 वर्षों का सफर, अटल जी का सपना, मोदी का संकल्प : वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई इस योजना ने पिछले ढाई दशकों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अब सशक्त गांव, विकसित भारत के संकल्प के साथ दूर–दराज के क्षेत्रों में विकास की नई राहें तैयार कर रही है।

तीसरे चरण का विस्तार, मार्च 2028 तक जारी रहेगी योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले तीसरे चरण की अवधि को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर मार्च 2028 कर दिया है। इस चरण के तहत 8584 किलोमीटर की 912 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। इन सड़कों ने कृषि मंडियों, स्कूलों और अस्पतालों तक ग्रामीणों की पहुंच को सुगम बनाया है। साथ ही योजना के लिए संशोधित वित्तीय बजट अब 83977 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है।

जनजातीय विकास और गुणवत्ता में भी आगे राजस्थान

पीएम–जनमन योजना के तहत बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में 43 किलोमीटर लंबी 14 सड़कों का निर्माण पूरा कर सहरिया जनजाति की बस्तियों की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। इसके अलावा, सड़कों के गुणवत्ता नियंत्रण में भी राजस्थान ने तमिलनाडू के साथ संयुक्त रूप से देश में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाया है।

सोमनाथ और भारत का अजेय जज्बा

—नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुननि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। 6 महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। **हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है** : प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्, अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन–पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार–चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा । यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों रक्षा की थी। माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई

पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। के बाद पूजा–पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, बीर वेगड़ाजो भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। 1940 के दशक में सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवम्बर, 1947 को, दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, "इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।" उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया।

दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होता नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डा. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। मुझे अक्तूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्तूबर, 2001 को, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी

मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री अडवानी जी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया। 11 मई, 1951 को अपने भाषण में डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा।

पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनैक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी सांझी सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले 1000 दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही सांझी चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है।

मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

मोदी जैसा नेता दुनिया में नहीं : एरिक सोलहेम

नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख एरिक सोलहेम ने उनकी जमकर प्रशंसा की हैं। सोलहेम ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताते हुए कहा कि पश्चिम देशों के नेताओं को उनकी 'ग्रीन ग्रोथ' नीति से बहुत कुछ सीखनें की जरूरत है। नॉर्वे के प्रतिष्ठित अखबार डेगेंस नेरिंग्सलिव में प्रकाशित अपने लेख मेंएरिक सोलहेम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चलने वाला मॉडल पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों से अपील की कि वे पीएम मोदी के विचारों को गंभीरता से सुनें। एरिक ने मोदी की जमकर की तारीफ सोलहेम ने लिखा कि किसी भी बड़े देश में ऐसा कोई नेता नहीं है। जिसे अपने देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जितना समर्थन और प्यार मिलता हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता 70 प्रतिशत के करीब है, जो उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करती है। उन्होंने पीएम मोदी के साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के सफर को भी असाधारण बताया। सोलहेम ने लिखा कि मोदी ने अपने जीवन और राजनीतिक करियर को अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के दम पर बनाया। भारत की तेज आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जो चीन सहित कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जो चीन सहित कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर इसी गति से विकास जारी रहा तो वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सोलहेम ने मोदी सरकार के दौरान देश में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी उल्लेखनीय बताया। पीएम मोदी को ग्रीन ग्रोथ का गारंटर बताते हुए भारत की सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की तारीफ की। उन्होंने गुजरात में बन रहे विशाल सोलर पार्क और आंध्र प्रदेश में विकसित हो रही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर–ब्रिड–हाईड्रो परियोजना का जिक्र किया।

'देश को कांग्रेस के कुचक्र से बचाया'

रिकॉर्ड कार्यकाल पर बोले, एक्सप्रेस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा देश

उथल–पुथल और अस्थिरता थी 2014 से पहले : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का कीर्तिमान बनाने के अवसर पर 10.06.2026 को कहा कि देश को कांग्रेस के कुचक्र से बचाया है। लोगों ने अब राजनीतिक स्थिरता और एक स्थिर सरकार के निर्णायक होने का महत्व समझ लिया है। 'विकसित भारत' का सपना किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है, बल्कि यह देश के हर व्यक्ति का संकल्प बन गया है। उन्होंने यहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की एक बैठक में कहा कि मेरे लिए, लोग ही ईश्वर का रूप हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के कई दशक अस्थिरता और उथल–पुथल से भरे थे, लेकिन अब लोग एक स्थिर सरकार का काम देख रहे हैं और उसक निर्णायक फैसलों की सराहना कर रहे है। राजग के 12 साल के शासन की एक बड़ी कामयाबी यह रही कि इसने देश को कांग्रेस के चंगुल से मुक्त कराया। कांग्रेस के धोखे के बाद लोगों ने हम पर भरोसा जताया। राजग परिवार के तौर पर हमने लोगों के उस भरोसे को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि देश को यहीं अहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे–धीरे ही होता है और बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था– हिंदू ग्रोथ रेट। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था– कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में न गवर्नेंस थी, न नीति, न नीयत और न ही निर्णय। अब देश देख रहा है कि एक्सप्रेस ग्रोथ रेट। काम अब तेजी से होते हैं।

रिकार्ड– नरेन्द्र मोदी आजाद भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का गौरव हासिल कर दिया। लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को 4399 दिन पूरे हो गए। इससे पहले यह रिकार्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम था ओर लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप मैं उनका कार्यकाल 4398 दिन का था।

21वीं सदी मोदी की सदी, सही समय पर सही नेता

प्रधानमंत्री की जीवन–यात्रा प्रेरणादायी है। मोदी नेतृत्व में हर क्षेत्र और वर्ग, खास कर वंचित वर्गों और पिछड़े इलाकों के कल्याण और विकास के लिए हुए उल्लेखनीय कार्य हुए है। **–द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति**

पीएम मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के गौरव को बहाल करने, सांस्कृतिक नवजागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने का रहा है। दुनिया एक सक्षम, सशक्त तथा नये भारत के उदय की साक्षी बन रही है। **–अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री,**

संकल्प से सिद्धि के इस शानदार दौर में भारत के विकास, सुरक्षा आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। **–नितिन नबीन, भाजपा अध्यक्ष**

आज, जब वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो हम सिर्फ एक रिकॉर्ड का ही नहीं बल्कि बदलाव के उस दौर का भी जश्न मना रहे हैं। जिसने देश के हर कोने को छुआ है।

–एन चंद्रबाबू नायडू सीएम, आंध्रप्रदेश

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा ढांचा काफी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, 'हमारी नीति साफ है। हम किसी को उकसाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति न तो अहंकार से बात करने की है न ही झुककर बात करने की, बल्कि दुनिया के साथ बराबरी के स्तर पर जुड़ने की है–**राजनाथ सिंह,केन्द्रीय रक्षा मंत्री**

केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और नरेन्द्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने का ऐतिहासिक उपलब्धि है। एक दशक की उपलब्धियों ने भारत की आर्थिक नींव को मजबूत किया है, नए अवसर पैदा किए है और विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। **–एचडी कुमार स्वामी, जेडीएस नेता और केन्द्रीय मंत्री**

प्रधानमंत्री मोदी 1.4 अरब भारतीयों के आत्म–सम्मान का प्रतीक है और वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान का प्रतिनिधित्व करते है। अगर महाराष्ट्र को विकास के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक मदद मिली है तो यह मोदीजी की वजह से है। **–एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र**

साधारण परिवार से निकलकर देश के शीर्ष निर्वाचित पद तक पहुंचने की अपनी उपलब्धि से मोदी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन गए हैं। मोदी की कहानी इस विश्वास को और पुख्ता करती है कि एक जीवंत लोकतंत्र में मेहनत और काबिलियत के दम पर हालात की बाधाओं को पार किया जा सकता है–**नीतिश कुमार,जदयू प्रमुख**

विश्व में सबसे ज्यादा तथा सबसे कम सम्मान पाने वाले राष्ट्राध्यक्ष		12 साल में मोदी सरकार ने क्या किया
1. नरेन्द्र मोदी, भारत	32 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान	• 721 साल बाद धार की भोजशाला में हुई पूजा।
2. व्लादिमीर पुतिन, रूस,	लगभग 25 अंतरराष्ट्रीय सम्मान	• 500 साल बाद मिला राम मंदिर अयोध्या।
3. शी जिनपिंग, चीन	लगभग 18 अंतरराष्ट्रीय सम्मान	• 500 साल बाद पावागढ़ के महाकाली मंदिर में फराई धर्म ध्वजा
4. नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका	250 से अधिक मानद उपाधियों और अनगिनत राजकीय सम्मान	• 31 साल बाद ज्ञानवापी में मिला फिर पूजा का अधिकार।
5. एंगेलला मर्केल, जर्मनी	लगभग 15 से अधिक प्रमुख वैश्विक सम्मान (कई यूरोपीय पुरस्कार शामिल)	**मोदी न होते तो क्या ये देखने को मिलता?**
6. डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका	लगभग 11 अंतरराष्ट्रीय सम्मान	
7. फ्रांसिसको गोतेरेस, तिमोर–लेस्ते	लगभग 10 विदेशी पुरस्कार	
8. फ्रांस्वा ओलांद, फ्रांस	लगभग 10 प्रमुख वैश्विक सम्मान	

मोदी अकेले विदेशों से लाए, तस्करी की हुई मूर्तियां :– नटराज, शिव, माँ उमा, कृष्ण, समेत 2500+ भारतीय मूर्तियां।
नेहरू से मनमोहन तक लाए सिर्फ 13 (1947 से 2013)

श्री अजेय कुमार बने राजस्थान के भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन)

भाजपा ने राजस्थान में संगठन महामंत्री के पद पर श्री अजेय कुमार की नियुक्ति कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव श्री अरूण सिंह ने 01.06.2026 को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। श्री अजेय कुमार वर्तमान में उत्तराखण्ड भाजपा में प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। नियुक्ति के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। श्री अजेय कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्टभूमि से आते हैं। संगठनात्मक कार्यों में उनका लंबा अनुभव रहा है। उत्तराखण्ड में उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, सदस्यता अभियानों और चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक शांत, अनुशासित, रणनीतिक संगठनकर्ता के रूप में रही है। प्रदेश में पूर्व संगठन महामंत्री श्री चन्द्रशेखर जी अगस्त 2017 से जनवरी 2024 तक इस पद पर रहे।

परिचय : –

- वर्ष 1997 में संघ के प्रचारक के रूप में श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से संगठनात्मक जीवन की शुरूआत की।
- श्रीनगर गढ़वाल, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में नगर प्रचारक के रूप में कार्य किया।
- ऊधमसिंह नगर में जिला प्रचारक का दायित्व संभाला
- अल्मोड़ा विभाग में विभाग प्रचारक के रूप में संगठन विस्तार एवं कार्यकर्ता निर्माण का कार्य किया।
- वर्ष 2009 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एवं बिजनौर विभाग के विभाग प्रचारक रहे।
- मेरठ प्रांत में प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के रूप में
- वैचारिक व संगठनात्मक प्रशिक्षण का दायित्व निभाया
- वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी, पश्चिमी उत्तरप्रदेश के क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) नियुक्त हुए।
- वर्ष 2019 से 2026 तक भाजपा उत्तराखण्ड के प्रदेश महामंत्री (संगठन) के रूप में कार्यकर्ताओं एवं संगठन का सफल मार्गदर्शन किया।

श्री अजेय कुमार जी एक अनुभवी, अनुशासित एवं समर्पित संगठनकर्ता है। जिन्होंने संघ और भाजपा में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उनका लंबा संगठनात्मक अनुभव, कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद और संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने की कार्यशैली उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। उत्तराखंण्ड भाजपा में प्रदेश महामंत्री (संगठन) के रूप में उन्होंने संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन में भूमिका निभाई है। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों तथा बूथ सशक्तिकरण के कार्यों को भी उनके अनुभव का भरपूर लाभ मिलेगा।

–मदन राठौड़, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा राजस्थान

श्री अजेय कुमार जी की राजस्थान भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) पद पर नियुक्ति संगठन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय है। यह नियुक्ति उनके वर्षों में समर्पण, संगठनात्मक कौशल, नेतृत्व क्षमता और परिणामोन्मुख कार्यशैली का सम्मान भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर भाजपा संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों तक उनका सफर कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्त्रोत रहा है।

–भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

मोदी सरकार– 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

जिनके जीवन का हर पल, सेवा और राष्ट्रहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिनके लिए जन कल्याण ही जीवन साधना है, ऐसे सेवा–व्रती नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की निरंतर प्रगति का साक्षी पूरा देश कह रहा है

–चम्पालाल रामावत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी कदमों पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत ने कई परिवर्तन देखे हैं और इन परिवर्तनों का मूल गरीबों का कल्याण है। अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष पूरा होने पर, मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों का उल्लेख किया और कहा कि ये सभी कदम लोगों को गरिमा और अवसर दिलाने के सरल उद्देश्य से प्रेरित हैं। उन्होंने 'एक्स' पर कहा, पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनों के मूल में गरीबों और वंचितों का कल्याण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा 'अंत्योदय' से प्रेरित रही है और उसका प्रयास हमेशा यह सुनिश्चित करना रहा है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से पीछे छूटे हैं। उन्होंने कहा, 'यह खुशी की बात है कि गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी ने कहा कि डीबीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता सीधे और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंन कहा, इससे खामियों में कमी आई है, कार्यकुशलता में सुधार हुआ है और शासन में विश्वास मजबूत हुआ है। इसी तरह 'गरीब कल्याण' को आगे बढ़ाने की यह यात्रा मानव सशक्तिकरण, विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गई है। मोदी ने 09 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 को शुरू हुआ

सबसे लंबे समय तक लगातार ये रहे पीएम

- नरेन्द्र मोदी : 26 मई 2014 से जारी (10 जून 2026 को 4,399 दिन)।
- पंडित जवाहर लाल नेहरू : 13 मई 1952 से 27 मई 1964 (4,398 दिन)
- इंदिरा गांधी : 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 (4,077 दिन)

12 साल, कई काम हुए, गरीबी घटी, सीमाएं मजबूत

गरीब कल्याण : 81+ करोड़ लोगों को प्रतिमाह मुफ्त राशन, 4+ करोड़ पीएम आास, 10.5+ करोड़ उज्जवला गैस कनेक्शन और 12+ करोड़ शौचालय निर्माण।

नारी शक्ति : 32+ करोड़ महिलाओं के जन–धन खते खुले, सेना में महिलाओं को मिला स्थायी कमीशन, 3+ करोड़ लखपति दीदी, 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 91+ लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त।

राष्ट्र निर्माण : 26 शहरों में फैला 1,100+ किमी का मेट्रो नेटवर्क, देशभर में दौड़ रही 164 वंदे भारत ट्रेनें, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील ब्रिज, पवन समुद्री पुल जैसे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चलर का निर्माण।

एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 164 हुई।

युवा शक्ति : लगभग 2 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग 40 लाख करोड़ के मुद्रा लोन, देशभर में 2.2 लाख स्टार्टअप्स, 10,000+ अटल टिंकरिंग लैब से नवाचार बढ़ा

स्वास्थ्य : 70+ के बुजुर्गों को भी 5 लाख रूपये का मुफ्त उपचार। 60+ करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुरक्षा, देशभर में 19,000+ जन–औषधि केंद्रों पर 90 प्रतिशत तक सस्ती दवाएं

राष्ट्र प्रथम : करीब 38,400 करोड़ का रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट, नक्सलमुक्त भारत का सपना साकार, आतंकवाद पर हो रहा कड़ा प्रहार, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, राजपथ बना कर्तव्य पथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की मुद्रा से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज।

किसान कल्याण : 4.3 लाख करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि, 4+ करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का फसल बीमा, 26+ लाख करोड़ की फसल खरीद एमएसपी

मिडिल क्लास : 12.75 लाख तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री, उड़ान योजना के तहत 1.6+ करोड़ यात्रियों ने की किफायती हवाई यात्रा, एमबीबीएस सीटों की संख्या 151 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.3 लाख हुई।

विरासत और विकास : अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल, महालोक और केदारनाथ धाम का कायाकल्प।

- अर्थव्यवस्था– चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति।
- जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद–370 हटाना।
- विदेश में साख बढ़ी।
- ग्लोबल साउथ लीडर।
- आत्मनिर्भरता पर जोर,
- रक्षा उत्पादन में छलांग

मोदी के आह्वान का विरोध व आलोचनाएं केवल राजनीतिक

—अवधेश कुमार

नरेंद्र मोदी द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों के हर संभव न्यूनतम उपयोग के साथ अन्य अपीलों व कदमों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में आलोचना व विरोध के स्वर ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने 10 मई को देशवासियों से मुख्यतः 3 अपीलें कीं, जिनमें एक साल तक सोने की खरीद टालने, गैर जरूरी विदेश यात्राएं न करने और पैट्रोल–डीजल की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग व सार्वजनिक यातायात का ज्यादा इस्तेमाल करना शामिल है। हालांकि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कहा जा रहा है कि चुनाव तक प्रधानमंत्री को संकट नहीं दिखा और अचानक दिख गया।

हालांकि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कहा जा रहा है कि चुनाव तक प्रधानमंत्री को संकट नहीं दिखा और अचानक दिख गया। पैट्रोल–डीजल के दाम बढ़े हैं तो आरोप यह है कि बस केवल चुनाव तक रोका गया था। इस तरह की अनेक आलोचनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने अपील के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में जाते समय अपने काफिले को कम किया तथा केवल 2 गाड़ियां दिखाई थीं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं अन्य मंत्रियों ने भी अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम की। इसके बाद पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें और निर्णय आए, जहां भाजपा सरकारों के मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या में कटौती की, स्वयं तथा सरकारी अधिकारियों के कार्यालय जाने की व्यवस्था में बदलाव किया और कई जगह सप्ताह में निश्चित दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति दी गई। इस तरह के कदमों से कई बार आशंका पैदा होती है मानो देश गंभीर संकट में है और लोगों से मितव्ययिता यानी कम खर्च करने को कहा जा रहा हो। विरोध और प्रतिक्रियाएं भी संदेहों को बढ़ावा देतीं हैं। वस्तुतः विरोध व आलोचनाओं में राजनीति ज्यादा है। कुछ गलतफहमियां भी पैदा की जा रही हैं। यह केवल विदेशी मुद्रा वाले खर्च में कमी करने संबंधी अपील है। फिर प्रधानमंत्री ने अपील की है, कोई नियम–कानून नहीं बना कि जिससे न मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। दूसरे, इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़े संकट में है। प्रधानमंत्री की अपील में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए 'वोकल फॉर लोकल' की भी बात है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति संतोषजनक है। विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग 697 अरब डॉलर है, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। महंगाई थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर नियंत्रण में है। किंतु भारत एक बड़ा आयातक देश है। हम कच्चे तेल का करीब 89 प्रतिशत आयात करते हैं तो सोने का 90 प्रतिशत से ज्यादा। हमारे कुल आयात बिल में 4 मदों में सबसे ज्यादा खर्च हैं। कच्चे तेल पर 2025–26 में कुल 134.7 अरब डॉलर का खर्च आया तो सोने पर 72 अरब डॉलर, खाने के तेल पर 19.5 अरब डॉलर और उर्वरक पर 14.5 अरब डॉलर।

ईरान अमरीका इसराईल युद्ध ने पूरी दुनिया में उथल–पुथल पैदा की है। होर्मुज संकट ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों के लिए समस्या पैदा की है, जिसका समाधान नहीं हो रहा। युद्ध कब समाप्त होगा, क्या मोड़ लेगा, कहना कठिन है। कोई वैश्विक संस्था इतनी प्रभावी नहीं जो व्यापार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समुद्री परिचालन आदि के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करा सके। पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला बाधित ही नहीं है उथल–पुथल के दौर में है। अभी तक आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की काफी हद तक भरपाई निर्यात तथा रेमिटैंस यानी विदेश में कार्यरत या रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा से हो जाती थी। इस कारण चालू खाते का घाटा हमेशा नियंत्रण में रहा। वर्ष 2024 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए धन की मात्रा 138 अरब डालर थो। अप्रैल से सितम्बर 2025 तक यह पिछले वर्ष के 64.7 अरब डॉलर से बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया था। खाड़ी युद्ध और वैश्विक संकट के कारण इसमें व्यापक कमी की संभावना पैदा हो गई है। इसी तरह वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं) 4.22 प्रतिशत बढ़कर 860 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जबकि आयात लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 979 अरब डॉलर तक पहुंचा। आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। किंतु मूल्य बढ़ते रहने के बावजूद आवश्यक आयातों को रोकना संभव नहीं। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो वित्त वर्ष 2026 में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 में 2.2 प्रतिशत तक जा सकता है। यह करीब 84.5 अरब डॉलर हो सकता है। यह घाटे में लगभग 3 गुना वृद्धि होगी। कच्चे तेल के दाम 26 फरवरी

के 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं। सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष हमने 11.40 लाख करोड़ का तेल आयात किया तथा 6.50 लाख करोड़ के आसपास का सोना। इस वर्ष तेल का आयात बिल 17 लाख करोड़, सोते का 10 लाख करोड़ हो सकता है, पिछले वर्ष हमने लगभग 470 टन सोना आयात किया। अगर 1 वर्ष तक सोना न खरीदें तो तूफान नहीं आ जाएगा

इनमें 50 प्रतिशत गिरावट आ गई तो 35–36 अरब डॉलर बचते हैं। अगर आप पैट्रोल–डीजल में 20 प्रतिशत की भी कटौती कर लेते हैं तो यह भी 35–36 अरब डालर हो जाता है। जहां तक तेलों के दाम बढ़ाने की बात है तो दुनिया में कौन–सा देश है जहां दाम नहीं बढ़े ? तेल कंपनियां प्रतिदिन करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठा रही हैं। सरकार पैट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए शुल्क घटा चुकी है। खाद की 2200 रुपए की बोरी 242 रुपए में मिल रही है। लगभग 82 देशों में पैट्रोल–डीजल की राशनिंग हो रही है। दक्षिण–पूर्व एशिया में तेल 50 प्रतिशत और यूरोप में 20 प्रतिशत महंगा हो चुका है। भारत में इसे नियंत्रित रखा गया है। आम लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि जब वैश्विक संकट है तो दाम बढ़ेंगे ही और अनेक कह रहे हैं कि ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे यह कम है। इसका अर्थ हुआ आम लोग इसके लिए तैयार हैं। विदेशी मुद्रा भविष्य की चुनौतियों के बीच सुरक्षा की गारंटी है। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट के कारण प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सरकार को 67 टन सोना विदेश में गिरवी रखकर 2000 करोड़ डॉलर का कर्ज लेना पड़ा था। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार को भी 45 दिनों में करीब 47 टन सोना और गिरवी रखना पड़ा, ताकि भारत 4000 करोड़ डॉलर कर्ज प्राप्त कर सके और आयात बिल का भुगतान संभव हो। वैसी नौबत फिरन आए, इसलिए आवश्यक है कि वैश्विक परिस्थितियों को समझते हुए देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री को अपील माने और भविष्य को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। (साभार : पंजाब केसरी)

ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर गई, अजेय रही टीएमसी

24 मई 2026 फाल्टा उप चुनाव के नतीजे ने अभिषेक और ममता बनर्जी के अभियान को चूर–चूर कर दिया

• फाल्टा के वोटिंग पैटर्न से एक बात तो साफ है कि मुसलमानों ने भी तृणमूल कांग्रेस से दूरी बना ली है और इन नतीजों के बाद फाल्टा नगरपालिका के सभी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। तृणमूल के जिन कार्यकर्ताओं से पहले लोग थर–थर कांपते थे, उन्हें घर कर पीटा जा रहा है, चोर–चोर के नारे लगाए जा रहे हैं।

• ममता बनर्जी और तृणमूल के विशाल प्रतीक चिन्हों को या तो हटा दिया गया या तोड़ दिया गया। ममता बनर्जी की पुरानी विश्वस्त सहयोगी संसद में सर्वाधिक मुखर सांसद रहीं काकोली दास गुप्ता ने ममता बनर्जी से संबंध तोड़ने की घोषणा की। भाजपा को 1,39,000 वोट मिले, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी आईएसएफ–सीपीआई (एम) उम्मीदवार को लगभग 37,000 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रही कांग्रेस को 6,700 वोट मिले और तृणमूल उम्मीदवार, जिसे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था, को केवल लगभग 4,000 वोट मिले। भाजपा 109021 मतों से जीती।

• फाल्टा और अन्य जगहों के मतदान रूझानों ने दिखाया कि पूरे चुनाव में हिन्दू वोटों का पूरी तरह ध्रवीकरण हुआ। बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता भाजपा के साथ गए, जबकि मुस्लिम वोट आईएसएफ–सीपीआई (एम) उम्मीदवार के पक्ष में चले गए। इससे साफ संकेत मिला कि अल्पसंख्यक वोटर बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस से दूर हो गए हैं।

मोदी सरकार 12 वर्ष – यह आया बदलाव

	2014–15	2024–2025
अर्थव्यवस्था	125.41 लाख करोड़	345 लाख करोड
रक्षा निर्यात	1,900 करोड़	23,000 करोड़
दशकीय महंगाई दर	8.1%	5.1%
राष्ट्रीय राजमार्ग	98,000 किमी	146 लाख किमी
हाईवे निर्माण गति	12 किमी / दिन	33 किमी / दिन
रेलवे विद्युतीकरण	22,000 किमी	45,000 किमी
एलपीजी कवरेज	55	100 के करीब
हवाई अड्डे	74	160 से अधिक
उज्जवला गैस योजना	14.52 करोड़	33.39 करोड़
एम्स	8%	15%
प्रति व्यक्ति आय	86647 रूपए	219575 रूपए
घर–घर कचरा संग्रहण	43 प्रतिशत	98 प्रतिशत
शिशु मृत्युदर / हजार	39	24
मातृ मृत्युदर / 1 लाख	130	97

• ताजा सर्वे के अनुसार 55 प्रतिशत लोग मानते है कि 12 वर्षों में बेहतर हुआ जीवन।

• इन वर्षों में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए लोगों ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली हैं मजबूती।

• लोगों ने कहा कि गृह विभाग तथा रक्षा विभाग में कार्य सबसे प्रभावशाली रहा है।

• 66%लोगों ने कहा विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ा है

• सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में विपक्ष असफल रहा

पश्चिम बंगाल : परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण

—राजनाथ सिंह, केन्द्रीय रक्षा मंत्री

'हे नूतन, देखा दिक आर–बार, जन्मेरो प्रथम 'शुभोखोन' (हे नवीन, एक बार फिर से सामने आओ, ठीक उसी तरह जैसे जन्म के समय वह पहला शुभ क्षण आया था)। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां केवल एक कविता का हिस्सा नहीं, बल्कि समय–समय पर स्वतः स्फूर्त और नवीन होने वाली बंगाल की आत्मा का आह्वान भी हैं। गुरुदेव भली–भांति समझते थे कि बंगाल समय के साथ केवल बदलता नहीं, बल्कि वह बार–बार बेहतर और नए रूप में पल्लवित होता है। गुरुदेव की जयंती पर गाई जाने वाली यह कविता नवजागरण और नवचेतना की प्रतीक है। यह प्रार्थना पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर, नए, उज्वल और रचनात्मक विचारों के स्वागत का आह्वान भी है। यह एक सुखद संयोग है कि गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती से कुछ दिन पहले ही, पश्चिम बंगाल कई दशकों के बाद नवजागरण का साक्षी बना है। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनाव कभी सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं था। यह चुनाव इस महान भूमि के खोए हुए गौरव को पुनस्थापित करने का एक अवसर था, एक ऐसा सभ्यतागत आह्वान, जो चुनावी समीकरणों और गणनाओं से कहीं ऊपर है।

आज जब पश्चिम बंगाल की चेतना और गौरव का अरुणोदय हो रहा है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बंगाल क्या है और बंगाल की चेतना का पुनर्जागरण किसे कहा जा सकता है? इसके लिए आवश्यक है बंगाल की शताब्दियों पुरानी चेतना को समझना और जानना। बंगाल सामाजिक चेतना का केंद्र होने से पहले जान और आध्यात्मिकता की पवित्र भूमि थी। 15वीं शताब्दी में नबद्वीप के गंगा तट पर एक युवा संन्यासी निमाई ने अपने कीर्तन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उस युवा संन्यासी को आज हम आदि संत चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिखाया गया भक्ति मार्ग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के साथ–साथ सामाजिक समरसता का अभियान भी था। चैतन्य महाप्रभु ने जात–पात और ऊंच–नीच के बंधनों को तोड़ा। यही चेतना **बाउल परंपरा** में भी दिखाई दी। बाउल परंपरा के फकीरों की पहचान जाति, धर्म या कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता की भावना थी। बाउल परंपरा के सबसे महान प्रवर्तक **लालन फकीर** थे। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया तथा मुस्लिम समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। वह बंगाल की उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे, जिसमें सहिष्णुता और सह–अस्तित्व का भाव समाहित था। विगत 3 शताब्दियों में, बंगाल और बंगाल के लोगों ने केवल भारत के सामाजिक नवजागरण आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। जब समाज अपनी जड़ता, कुरीतियों और विकृत प्रपराओं के बोझ तले दब चुका था, तब **राजा राममोहन राय** ने न तो परंपरा का समूल रूप से परित्याग किया और न ही तर्कशून्य तरीके से उसको उचित ठहराया। उन्होंने लोगों को आत्मबोध कराकर, समाज को भीतर से सुधारने का मार्ग चुना। सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल समाज सुधार से जुड़ा आंदोलन नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक तप था। **ईश्वर चंद्र विद्यासागर** ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा, विशेषकर नारी शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मंत्र बना दिया।

बंगाल के ही **बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय** ने 'वंदे मातरम्' जैसा अमर मंत्र राष्ट्र को दिया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बल दिया और सदियों से सोए हुए देश को जगा दिया। बंगाल ने ही भारत की सबसे पहली महिला चिकित्सक **डा. कादम्बिनी गांगुली** जी को जन्म दिया, जिन्होंने सभी को, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया। बंगाल की ही धरती पर जन्मे, प्रखर राष्ट्रवादी **डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी** ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। संभवतः बंगाल की धरती ने जितनी भी विलक्षण प्रतिभाओं और महान लोगों को जन्म दिया, उनमें सबसे देदीप्यमान और प्रबुद्ध **स्वामी विवेकानंद** को कहा जा सकता है। शिकागो में दिया गया उनका भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने पूरे विश्व को वेदान्त और भारत के महान सभ्यतागत मूल्यों से परिचित कराया।

ये सब बातें बंगाल की आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। यही उसकी सनातन और शाश्वत पहचान रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को इसी दृष्टि से देखते हैं। यह अतीत में लौटने की आकांक्षा नहीं है, न ही यह

आधुनिकता की चाह में पराई सभ्यता को प्रतिछाया बनने की लालसा है। यह वह दृष्टि है जो बंगाल को पुनः जागृत करना चाहती है, ताकि वह अपने पूर्ण सामर्थ्य के बल पर फिर से अपने सर्वोच्च वैभव को प्राप्त कर सके। दुर्भाग्यवश, लंबे समय तक बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों और राजनीतिक वर्गों ने अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को बोझ समझा और उसे हेय दृष्टि से देखा। सभ्यता, धर्म, संस्कृति और बंगाल की चेतना की बात करने वाले लोगों और उनकी आवाज को दबाया गया। परंपरा को पिछड़ापन समझा गया और आधुनिकता के नाम पर औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा दिया गया। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल ने दशकों तक विकासहीनता, अराजकता, संस्थागत पतन और वैचारिक जड़ता का दंश झेला। बंगाल में हुआ यह चुनाव और परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ जनादेश भी है, जिन्होंने बंगाल को उसके मूल से दूर किया। बेलूर मठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मिक जुड़ाव, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और सुशासन को 'सेवा' के रूप में देखने का उनका दृष्टिकोण, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि 'प्रधान सेवक' बंगाल के विकास और पुनर्जागरण को एक पावन दायित्व मानते हैं, जिसे वह अपने 'प्रधान धर्म' और 'प्रधान कर्म' के रूप में निभा रहे हैं। इसलिए बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण का अर्थ कई दशकों से उपेक्षित और जीर्ण–शीर्ण हो चुके इंफ्रास्ट्रक्कर का निर्माण तो है ही, साथ ही इसका अर्थ उन घाटों को पुनर्जीवित करना भी है जहां चौतन्य महाप्रभु के कीर्तन ने लोगों को भाव–विभोर किया था। इसका अर्थ उन शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त करना भी है जिनका स्वप्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा था। इसका अर्थ उन आदिवासी भाइयों–बहनों को गरिमा, सम्मान और अवसर देना भी है जो सदियों से बंगाल में रहते आए हैं। इसका अर्थ लंबे समय से उपेक्षा झेल रहे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना भी है। पिछले कुछ दशकों में भय और कुशासन के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो पश्चिम बंगाल का स्वर्णिम युग बीत चुका हो। किंतु आज बंगाल एक बार फिर नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ समृद्धि एवं शंति से भरे नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के साथ बनने वाली पहली भाजपा सरकार गुरूदेव के द्वारा वर्णित 'नूतन' भावना के साथ सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी और बंगाल की प्रतिष्ठा और समृद्धि के साथ बंगाल का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगी।

घुसपैठियों पर कसी जाएगी नकेल : अमित शाह

केन्द्र सरकार ने अवैध प्रवासियों और अन्य असामान्य कारणों विभिन्न राज्यों में आबादी के अनुपात में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को इस समिति के गठन की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) होंगे और जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस,), बालाजी श्रीवास्तव, (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति एक वर्ष में रिपोर्ट देगी। जरूरी होने पर गृह मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। गौतलब है कि देश में असम, पश्चिम बंगाल और कई अन्य सीमावर्ती राज्यों में पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ तथा अन्य कारणों से आबादी के अनुपात में बदलाव हो रहा है। यह समिति इस बदलाव के कारणों व प्रभाव का अध्ययन करेगी। **यह काम करेगी कमेटी :–**

- अवैध अप्रवास सहित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करना।
- ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना, जैसे सीमा पर गतिविधियां (अवैध प्रवास) आर्थिक अवसर और अन्य सामाजिक–पर्यावरणीय कारक। इन परिवर्तनों के पीछे अंतर्निहित कारकों की पहचान करना, जिसमें अवैध अप्रवास, असामान्य बसावट पैटर्न और नियोजित प्रवास शामिल है।
- धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर सरंचनात्मक जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण करना, विशेष रूप से समान रूझानों से अलग होने पर। देश में पहले से ही रहने वाले अवैध प्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थाई परिचालन प्रणाली की सिफारिश करना।
- ऐसे रूझानों की निरंतर निगरानी के लिए सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना। अवैध प्रवास और इससे होने वाले जनसांख्यिकीय असंतुलन से संबंधित मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना। समिति जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों, जिनमें अवैध प्रवास भी शामिल है, से निपटने के लिए किसी अन्य उपाय, जिसे वह उचित समझे, की सिफारिश कर सकती है।

आत्मनिर्भर भारत : स्वदेशी चेतना का पुनर्जागरण

–भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान किया है, वह केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह महात्मा गांधी के 'स्वदेशी', पं. दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' और आधुनिक तकनीकी भारत के त्रिवेणी संगम की अवधारणा है। इस विचार में स्वदेशी केवल उत्पादन की नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र की पहचान है।

भारत का स्वदेशी भाव हमारी परंपरा की जड़ों में गहराई से बसा है। हमारे गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाइयां थे और उनमें उत्पादन, विनिमय और उपभोग का अपना संतुलित तंत्र था। अंग्रेजी शासन ने इस तंत्र को तोड़कर भारत को विदेशी वस्तुओं का उपभोक्ता बना दिया।

महात्मा गांधी ने इस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए 'स्वदेशी' को स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। खादी, चरखा, नमक और हस्तशिल्प जैसी साधारण वस्तुएं राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान बन गईं। गांधीजी कहते थे– 'स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि आत्मगौरव का प्रतीक है।'

आत्मनिर्भरता का नया युग

आज वही स्वदेशी चेतना आधुनिक रूप में लौट रही है। प्रधानमंत्री मोदी का 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल से ग्लोबल' का मंत्र उसी भावना का नया संस्करण है और आत्मनिर्भरता का अर्थ वैश्विक मंच पर भारत की विशिष्ट पहचान स्थापित करना है।

गत एक दशक में भारत ने आत्मनिर्भरता के जिस मार्ग पर कदम रखे हैं, उसने विश्व को चकित किया है। वर्ष 2014 में भारत 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में 142वें स्थान पर था, अब वह शीर्ष 63 देशों में शामिल है। 'मेक इन इंडिया' और 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' जैसी योजनाओं ने विनिर्माण क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत की है। मोबाइल निर्माण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो देश एक दशक पहले तक लगभग पूर्ण आयातक था. आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। तेजस लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट, आकाश मिसाइल और स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत इसके साक्षात प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 'चिप से शिप तक भारत में' का संकल्प अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में मूर्त रूप ले रहा है। यह 'स्वदेशी 2.0' का वास्तविक प्रारूप आत्मनिर्भर भारत का तकनीकी रूपांतरण है

आर्थिक उपनिवेशवाद से मुक्ति की राह

राजनीतिक स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रभाव के कई स्वरूप कायम हैं। विदेशी ब्रांड, परामर्श कंपनियां, डेटा नियंत्रण और उपभोक्ता मनोविज्ञान पर विदेशी प्रभुत्व आदि को आधुनिक आर्थिक उपनिवेशवाद का नया चेहरा माना जाता है।

स्वदेशी 2.0 का उद्देश्य अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि नीति, तकनीक और विचार के स्तर पर भी आत्मनिर्भरता स्थापित करना है। राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा, घरेलू कसल्टेंसी को प्रोत्साहन, स्थानीय अनुसंधान और भारतीय नवाचार को प्राथमिकता देना ही इस युग की नई स्वतंत्रता का घोष है।

गांधीजी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। आज आवश्यकता है कि हम विदेशी ब्रांडों, डिजिटल वर्चस्थ और उपभोक्तावादी निर्भरता की बेड़ियों को त्यागे। यही आधुनिक भारत का आर्थिक स्वराज्य होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भरता मॉडल केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वालो विकास प्रक्रिया है। जनधन योजना ने 55 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा, उज्वला योजना ने 10 करोड महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाई, और स्वनिधि योजना ने छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया।

नया आत्मविश्वास

अब डिजिटल इंडिया और गति शक्ति योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक नेटवर्क से जोड़ दिया है। यूपीआई ने वित्तीय लेन–देन को गांव–गांव तक पहुंचा दिया है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास की सजीव झलक है।

केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष 305 उत्पादों पर जीएसटी में कमी से आम उपभोक्ताओं को राहत और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला है। भारत अब आत्मनिर्भरता को केवल देश की नीति नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वर्ष 2024–25 में भारत का निर्यात 500

अरब डॉलर के करीब पहुंचा है। फार्मा क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा उत्पादक बना हुआ है।

कोरोना महामारी के दौरान भारत ने 'वैक्सीन मित्र' बनकर विश्व को जीवनरक्षक वैक्सीन दी, जहां आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से जुड़ गई। राजस्थान ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को धरातल पर साकार किया है। सौर ऊर्जा, अनाज, कृषि–प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और एमएसएमई के क्षेत्र में राज्य ने 'मेड इन राजस्थान' की पहचान को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा है। जैसलमेर और जोधपुर अब अक्षय ऊर्जा के केंद्र बन चुके हैं, जबकि जयपुर स्टार्टअप इनोवेशन का नया गढ़ बन रहा है। यह दिखाता है कि स्वदेशी अब केवल नारा नहीं, बल्कि नीति का अंग बन चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, 'आत्मनिर्भर भारत, 21वीं सदी का स्वराज्य है।' यह स्वराज्य राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अब समय है कि आत्मनिर्भरता केवल सरकारी योजनाओं तक सोमित न रहे, बल्कि जन–जन की जीवनशैली बने। जब प्रत्येक नागरिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देगा, व्यापारी भारतीय वस्तुओं को अपने स्टोर में प्रमुखता देगा और नीति–निर्माता विदेशो प्रभाव से मुक्त निर्णय लेगे, तभी भारत सच्चे अधों में आत्मनिर्भर बनेगा। महात्मा गांधी का चरखा, पं. दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत–तीनों मिलकर आज 'स्वदेशी 2.0' को अर्थ देते हैं। यही भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर आत्मगौरव नवाचार और समद्धि से प्रकाशित करेगा।

SIR पर आया फैसला : 13 राज्य–UT में 7.41 करोड़ नाम कट चुकें... आयोग के पास वैलिड रीजन

सुप्रीम कोर्ट बोला– SIR वैध और संवैधानिक... यह चुनाव आयोग का अधिकार विपक्ष को लगा झटका झूठ हुआ नाकाम

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर–नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजा जाए। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तरप्रदेश से कटे। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडू और पुडुचेरी में भी एसआईआर कराया गया। **किसी की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं** : अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जांच किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं मानी जाएगी। अगर चुनाव आयोग को लगे कि किसी व्यक्ति के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या वह जांच में सफल नहीं हुआ है, तो वह मामला नागरिकता कानून के तहत अंतिम निर्णय के लिए केन्द्र सरकार की सक्षम प्राधिकरण के पास भेज सकता है। वहां संबंधित इस्तावेजों पर निर्णय होगा। **एसआईआर आज विपक्ष के दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, सन्ताप, शोक और तकलीफ का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।**

सीमा के 15 किमी दायरे में सभी अवैध ढांचे ध्वस्त करें : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ 'कतई बर्दाश्त न करने की नीति' को संख्ती से लागू करने और पिछले कुछ वर्षों में बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने जिला मजिस्टेट्रों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बैंकिंग लेनदेन के कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के वित्त पोषण स्त्रोतों की जांच करने फर्जी खातों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सीमावर्ती जिलों को अपराधों और मादक पदार्थों की समस्या के स्त्रोतों, स्वरूपों और नेटवर्क का गहन अध्ययन करने और स्थायी समाधान विकसित करने का निर्देश दिया गया है। ताकि ये समस्याएं दोबारा न उभरें। श्री शाह ने नागरिकों, सरकारी तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवच तैयार करने पर जोर दिया।

ड्रिफ्ट से डिलीवरी तक : राजस्थान में भजनलाल शर्मा का 2 वर्षीय रिपोर्ट कार्ड

—शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा

राजस्थान सरकार के शासन की जितनी गहराई से जांच की जाए, कांग्रेस प्रशासन को सत्ता से हटाए जाने के 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद, उतना ही स्पष्ट होता है कि अशोक गहलोत का 5 वर्षीय शासन (2018–2023) राज्य के लिए व्यर्थ का दौर साबित हुआ। पार्टी के अंदरूनी विवाद, खासकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच, अक्सर गहलोत को अपनी कुर्सी बचाने में उलझाए रखते थे, न कि प्रभावी शासन में अंततः 2023 के चुनावों में मतदाताओं ने उनकी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। वर्तमान भाजपा सरकार ने गहलोत सरकार की इन गलतियों से सबक लिया प्रतीत होता है। पिछले 2 वर्षों में रास्थान एक शांत, अधिक स्थिर और ठोस शासन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें परियोजनाओं के क्रियान्वयन और डिलीवरी की तेज गति पर ध्यान दिया गया है।

पानी–सभ्यतागत प्राथमिकता का समाधान : एक ऐसे राज्य में जहां पानी की कमी ने इतिहास और आदत दोनों को आकार दिया है, जल प्रबंधन सिर्फ नीति का विषय नहीं, बल्कि सभ्यतागत चिंता है। राम जल सेतु लिंक जैसी बड़ी परियोजनाओं की ओर कदम, जिसमें 26,000 करोड़ रूपए के कार्य आदेश जारी किए गए है, साथ ही यमुना जल के उपयोग के प्रयास (एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित और डी.पी.आर. कार्य प्रगति पर) पैचवर्क समाधान की बजाय दीर्घकालिक रणनीति का संकेत देते हैं। इसी बीच, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन का विस्तार 14 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंच चुका है।

इंफास्ट्रक्चर–आर्थिक धमनियों का निर्माण : 42,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का विस्तार और उन्नयन, जिसमें निर्माण और अपग्रेडेशन पर 29,333 करोड़ रूपये खर्च किए गए, सिर्फ अमूर्त कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में सड़के आर्थिक धमनियां है। वे तय करती है कि माल कितनी तेजी से पहुंचता है, बच्चे स्कूल कितनी आसानी से जाते हैं। और दूरदराज के समुदाय राज्य के अन्य हिस्सों से कितना जुड़ा महसूस करते हैं यहां पुरानी दुनिया का एक तर्क है, सड़कें बनाओ, विकास अपने आप आएगा।

ऊर्जा क्रांति–खेतों और भविष्य को शक्ति : ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उत्पादन क्षमता में 8261 मेगावाट की वृद्धि हुई। दिन में खेतों तक बिजली पहुंचाना किसानों की दिनचर्या बदलताहै अनिश्तता कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। पीएम कुसुम योजना के तहत 2,884 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई और 2.10 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए, 22 जिलों में अब दिन में बिजली उपलब्ध है। सौर ऊर्जा पर समानांतर जोर 59,000 सोलर पंपों (921 करोड़ रूपए सब्सिडी) और पी. एम. सूर्य घर योजना के तहत 1.31 लाख रूफटॉप सोलर प्लांटों से स्पष्ट हैं।

कृषि–किसानों के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा जाल : कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनी हुई है। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रूपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए गए। 50,802 करोड़ रूपए के ब्याज–मुक्त फसल ऋण, वितरित किए गए, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6473 करोड़ रूपए के क्लेम किसानों को दिए गए। इनके साथ 48591 करोड़ रूपए की बिजली सबसिडी और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन एक सुरक्षा जाल बनाते हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण : लाडो (लाडली) प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रूपए कर दी गई। 20 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रूपए की गई। मां वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी प्रदान करती है, जिसका लाभ अब तक 2.26 लाख से अधिक महिलाओं को मिल चुका है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 10 प्रतिशत की कमी आई है। वृद्ध, विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगों और छोटे सीमांत किसानों की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह कर दी गई। मुख्यमंत्री मंगल शिशु बीमा योजना के तहत 14 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त बीमा पॉलिसी जारी की गई।

कानून–व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा : अपराधों में कुल 14 प्रतिशत औसत कमी (महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित) कानून–व्यवस्था में सुधार का संकेत देती है, हालांकि ऐसे दावों की जांच और निरंतरता आवश्यक है। आवास, रोजगार और औद्योगिक प्रोत्साहन प्रधानमंत्री आवास योजना 1 केर के तहत 2 लाख से अधिक घर पूरे कर जरूरतमंदों को सौंपे गए। लगभग 1. 25 लाख नियुक्तियां की गईं, विभिन्न चरणों में 1.33 लाख

पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। निजी क्षेत्र में अब तक लगभग 3 लाख रोजगार प्रदान किए गए। 2026 के लिए 'सवा लाख नौकरी' कैलेंडर जारी किया गया। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 2 वर्षों में 34 से अधिक क्षेत्र विशेष नीतियां जारी की गई। **आर्थिक मील के पत्थर** : प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपए के पार, अब 2,02,349 रु. हो गई है। आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनैस प्रयासों से औसत जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर 12.25 प्रतिशत तक बढ़ गई। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वैस्टमैंट समिट 2024 में 35 लाख करोड़ रुपए के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। केंद्रीय योजनाओं में राजस्थान 11 में प्रथम, 5 में द्वितीय और 7 में तृतीय स्थान पर है (कुछ रिपोर्टों में तृतीय 9 में)। सभी में जो सबसे अलग दिखता है वह है मंशा की एक निश्चित निरंतरता। यह शोबाजी का जोरदार मॉडल नहीं, बल्कि स्थिर शासन का है। इसमें भव्य इशारे या व्यापक घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि यह संचय से काम करता है–योजना–दर–योजना, क्षेत्र–दर–क्षेत्र। कई मायनों में यह पुरानी प्रशासनिक शैली की याद दिलाता है, जहां प्रगति अचानक छलांगों से कम और स्थिर, क्रमिक लाभों से अधिक मापी जाती थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उस यह पर चलते दिखते हैं। पूर्णतः नहीं, चुनौतियों के बिना नहीं लेकिन एक जमीनी व्यावहारिकता के साथ

तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनाक्रोश से भाजपा भी अचंभित

लोग उन जगहों को ढूंढने में लगे है, यहां तक कि ड्रोन का उपयोग भी कर रहे हैं, जहां तृणमूल नेताओं ने लूट छुपा रखी है

राष्ट्रीय स्तर पर जाने–माने वरिष्ठ सांसद और तथाकथित प्रोफेसर सौगत रॉय को उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ ने ''चोर–चोर'' के नारों के साथ घेर लिया। जब एक स्थानीय पुलिस थाने से बाहर निकले, तब लोगों ने उनका जोरदार विरोध किय। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिसकर्मियों को उन्हें सुरक्षा देकर उनकी कार तक पहुंचाना पड़ा।

पुलिस सुरक्षा के बीच भी प्रोफेसर रॉय पर सड़े हुए अंडे फेके गए। उनकी कार पर कच्चे अंडे मारे गए और बुजुर्ग सांसद के खिलाफ लोग अपशब्द बोलते रहे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वे दोबारा अपने क्षेत्र में कदम न रखें। पूरे बंगाल में अब आम लोग पूर्व सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ बेहद गुस्से में है। तृणमूल कांग्रेस के नगर पार्षदों, चैयरमैनों और अन्य नेताओं को उनके छिपने के ठिकानों या जब वे अपने नगरपालिका दफ्तरों का दौरा कर रहे होते हैं, तब खोज–खोजकर पकड़ा जा रहा है। हालात जिस तरह बन रहे है, उससे लगता है कि लोगों की सत्ताधारी पार्टी के गुंडों द्वारा वर्षों से किए जा रहे अत्याचार और जुल्म का बदला लेने से रोकना मुश्किल हो सकता है। भाजपा प्रवक्ताओं ने संभावित हमलों की आशंका स्वीकार की है, लेकिन यह भी कहा कि खासकर दूरदराज गांवों में स्थिति को नियंत्रित करना हमेशा आसान नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में गांव वाले एकजुट होकर अपने पुराने जुल्म करने वालों को पकड़ रहे है और उनसे वह पैसा वापस मांग रहे है। जो इन ताकतवर स्थानीय नेताओं ने गरीब और कमजोर लोगों से जबरदस्ती वसूला था। साथ ही, पुलिस छापों में भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हो रही है। एक मामले में कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। बदुरिया गांव में पुलिस और ग्रामीणों ने बड़े–बड़े बैग और कई तरह के पैकेट बरामद किए, जिनमें नकदी भरी हुई थी। पूरी घटना बेहद रोमांचक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने जूट के घने खेतों के बीच कुछ ऐसे स्थानों की जानकारी दी थी, जहां पौधों के साथ छेड़छाड़ के निशान दिख रहे थे। ड्रोन जांच में भी खेत में असामान्य गतिविधि दिखाई दी। जब ग्रामीणों और पुलिस की टीम वहां पहुंची, तो उन्हें लाल कपड़े के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। पास जाकर जांच और शुरूआती खुदाई में बडे बैग मिले। कुछ छह बैग बरामद हुए, जिनमें लगभग 2.84 करोड़ रूपए पाए गए। इसके अलावा एक नगरपालिका पार्षद के घर के पास मौजूद एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से करीब 84 लाख रूपये मिले। नगरपालिका निगम का चैयरमैन, जो पहले राजमिस्त्री और ड्राईवर था, चैयरमैन बनने के बाद करोड़ों रूपये इकट्ठा कर चुका था। अब इलाके के लोग इकटठा होकर उस पैसे की वापसी की मांग कर रहे है, जो पार्षदों ने वर्षों में लोगों वे वसुलते थे। एक जगह प्रदर्शनकारी एक नगरपालिका पार्षद के दफ्तर में पहुंच गए और अपना पैसा वापस मांगने लगे। कलकत्ता के पास हाबड़ा में घिरे हुए निगम पार्षद ने लिखकर वादा किया कि वो 84 लाख रूपये लौटा देगें, जो उन्होंने जमा किए थे। गोबरडांगा गांव में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से 900 से ज्यादा गोलियां और हथियार बरामद किए गए। पूर्वी कलकत्ता के तंगरा इलाके में तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय दफ्तर से आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों के ढेर मिले। नगरपालिका के चैयरमैन जीवन साहा से पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर, चंद्रकोना गांव के उत्तम सेन पर आवास योजना के घर दिलाने के नाम पर धन के गबन के आरोप लगे है। उन्होंने अपने इलाके के गरीब ग्रामीणो से पैसे लिए थे, जो अब अपने पैसों को लेकर परेशान है। अब यह ''राम भरोसे'' है कि राज्य में कोई बड़ी घटना न हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में जय श्री राम के नारे गूंज रहे है। (साभार : राष्ट्रदूत)

राम जल सेतु लिंक परियोजना

राजस्थान के जल भविष्य की नई धारा

–राजेन्द्र राठौड़, पूर्व मंत्री राजस्थान

राजस्थान सदियों से जल संकट, सुखा और आसमान वर्षा की चुनौती से जूझता रहा है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के बीच जल उपलब्धता की विषमता ने न केवल कृषि और उद्योग को प्रभावित किया, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन स्तर पर भी असर डाला। ऐसे समय में राम जल सेतु लिंक परियोजना के अन्तर्गत संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना रास्थान के भविष्य को पुनर्परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक अभियान बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों निरंतर मॉनिटरिंग और केन्द्र सरकार के साथ सक्रिय समन्वय के कारणयह परियोजना अब तेजी से धरातल पर आकार ले रही है।

जल संरक्षण जन अभियान

विशेष रूप से गंगा दशहरे के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 25 मई को टोंक जिले के बीसलपुर बांध पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरूआत करना इस परियोजना को आमजन से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री बीसलपुर बांध पर जल पूजन करेंगे तथा इसके साथ ही गलवा बांध से ईसरदा से बांध बरेठा का हवाई सर्वेक्षण भी करेगे। यह कार्यक्रम जल संरक्षण, नदी संस्कृति और भविष्य की जल सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

पेयजल उपलब्ध होगा

यह परियोजना मूल रूप से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी के विस्तारित और एकीकृत स्वरूप के रूप में विकसित की गई है। इसका उद्देश्य कूनो, पार्वती और और कालीसिंध नदियों के अतिरिक्त जल को बनास, बाणगंगा, गंभीरी, रूपारेल और साबी नदी बेसिनों तक पहुंचाना है, ताकि राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अर्थात् करीब सवा 3 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही लगभग 4 लाख 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा व जहां केवल एक फसल हो रही थी, वहां दो फसल की सुविधा विकसित होगी।

महत्वपूर्ण समझौता हुआ

औद्योगिक क्षेत्रों को भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 91 हजार करोड़ रूपये है। जिसमें भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की बड़ी राशि भी शामिल हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हुए इस समझौते ने परियोजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता के स्तर पर पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को जनकल्याण और भविष्य की जल सुरक्षा से जोड़ते हुए लगातार समीक्षा बैठक की, वित्तीय स्वीकृतियों को गति दी और केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर परियोजना के अटके हुए पहलुओं को आगे बढ़ाया।

राज्य के 17 जिलों को लाभ

यही कारण है कि जो योजना वर्षों तक केवल चर्चा में थी, वह अब बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के रूप में दिखाई देने लगी है। परियोजना से राज्य के 17 जिलों झालावाड, कोटा, बारां, बूंदी, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, डीग, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, बयावर, कोटपूतली बहरोड़, धौलपुर और खैरथल तिजारा को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इन जिलों में पेयजल उपलब्धता सुधरेगी, सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा। और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका बहुस्तरीय जल प्रबंधन ढांचा है। बारां जिले में रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज का निर्माण प्रगति पर है। जहां एकत्रित जल की नवनेरा बैराज तक पहुंचाया जाएगा।

बांधों और जलाशयों तक

नवनेरा बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके बाद इस जल को पंप हाउस और चंबल एक्वाडक्ट के माध्यम से आगे विभिन्न बांधों और जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। ईसरदा बांध का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है और इसमें इस वर्ष जल भराव किया गया है। लगभग 1038 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित यह बांध परियोजना की प्रमुख कड़ी माना जा रहा है। वहीं नवनेरा बैराज पर लगभग 1117 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। परियोजना का तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण और गौरवपूर्ण भाग चंबल एक्वाडक्ट है।

2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य

इसका निर्माण बूंदी जिले के गुहाटा गांव के पास हो

रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट है। इसकी लंबाई लगभग 2280 मीटर तथा क्षमता 250 क्यूमेक्स है। इसके निर्माण में 5060 पाइल्स और 50 पियर्स का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में हजारों पाइल्स का कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रतिदिन बड़े स्तर पर कंक्रीटिंग कार्य जारी है। यह परियोजना केवल बांध और नहर निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विशाल फीडर नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। मेज से गलवा, गलवा से ईसरदा और गलवा से बीसलपुर तक लंबी फीडर नहरों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन सभी कार्यों को वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय प्रक्रियाएं पूर्ण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लगभग 23 हजार करोड़ रूपये के कार्यों को स्वीकृति दिलाई। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी बैराज निर्माण के लिए भी 780 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई। भरतपुर क्षेत्र के लिए ईसरदा से खुरा चैनपुरा होते हुए बंध बरेठा तक फीडर निर्माण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 2905 करोड़ रूपये की लागत वाले इस कार्य के लिए सर्वे, भूमि अधिग्रहण और वित्तीय प्रक्रियाएं पूर्ण कर निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। इससे भरतपुर संभाग क्षेत्र के भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धोलपुर में पेयजल हेतु स्थायी लाभ मिलेगा।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इसी प्रकार मोर सागर कृत्रिम जलाशय और उससे जुड़े फीडर तंत्र के निर्माण पर लगभग 4799 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। बीसलपुर से टोरडी सागर, फिर लाम्बा हरीसिंह और भीम सागर होते हुए मोर सागर तक जल पहुंचाने की व्यापक योजना बनाई गई है, जिससे अजमेर संभाग के जिलों को पेयजल हेतु स्थायी लाभ मिलेगा।

जयपुर, दौसा और अलवर क्षेत्र के लिए भी अलग अलग फीडर और कन्वेंस सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। जयपुर के लिए लगभग 2196 करोड़ रुपये तथा दौसा एवं अलवर क्षेत्र के लिए लगभग 3995 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं से राजधानी क्षेत्र सहित कई औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों को दीर्घकालिक जल सुरक्षा प्राप्त होगी। यह परियोजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक संरचना पर दूरगामी प्रभाव डालने वाली है।

सिंचाई पर निर्भरता मजबूत

जल उपलब्धता बढ़ने से किसानों की सिंचाई पर निर्भरता मजबूत होगी, भूजल दोहन कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की समस्या में कमी आएगी। औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित जल आपूर्ति मिलने से निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गंगा दशहरा पर प्रारंभ हो रहा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह जल संरक्षण को सामाजिक चेतना का अभियान बनाने का प्रयास है। बीसलपुर बांध पर जल पूजन और प्रमुख बांधों के हवाई सर्वेक्षण के साथ ही भरतपुर के गंगा मंदिर में गंगा आरती और सुजान गंगा में दीपदान के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह संदेश दे रहे हैं कि राजस्थान का विकास जल संरक्षण और जल प्रबंधन की मजबूत नींव पर ही संभव है।

जन विश्वास की परियोजना

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना को राजनीतिक घोषणा से आगे बढ़ाकर जन विश्वास की परियोजना बनाया है। उनकी कार्यशैली में निरंतर फील्ड मॉनिटरिंग, समयबद्ध लक्ष्य और प्रशासनिक जवाबदेही स्पष्ट दिखाई देती है।

यही कारण है कि परियोजना के विभिन्न पैकेजों पर एक साथ बड़े पैमाने पर कार्य प्रगति पर है। राजस्थान जैसे जल संकटग्रस्त राज्य में राम जल सेतु लिंक परियोजना वास्तव में जीवनरेखा सिद्ध हो सकती है। इसी निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पूर्ण होने पर आने वाले दशकों में राजस्थान की जल व्यवस्था, कृषि विकास और औद्योगिक प्रगति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यह केवल नदियों को जोड़ने की योजना नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य को जोड़ने का अभियान है और इस अभियान को गति देने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका निर्णायक रूप से उभरकर सामने आई है।

भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस हुई पस्त
हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव

नगर निकाय	भाजपा	कांग्रेस
सोलन	10	6
मण्डी	12	1
धर्मशाला	11	5
पालमपुर	1	7

सोलन भी जीता भाजपा ने, टूट गया कांग्रेस का गढ़, अबकी बार हिमाचल में भाजपा सरकार

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान

परंपरा, पर्यावरण और जनभागीदारी का संगम

—लालचंद कटारिया, पूर्व कृषि मंत्री

राजस्थान सदियों से जल प्रबंधन की अद्भुत परंपराओं वाला प्रदेश रहा है। यहां पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और लोक आस्था का आधार माना गया है। मरूस्थलीय परिस्थितियों के बीच राजस्थान के लोगों द्वारा बूंद–बूंद पानी को संजोने की विकसित परंपराएं आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं। बावड़ियां, जोहड़, तालाब, टांके और कुएं जैसी जल संरचनाएं समाज की सामूहिक चेतना के प्रतीक रहे हैं।

जल संकट एक वैश्विक चुनौती

आज जल संकट एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है। इन स्थितियों में गंगा दशहरे के पावन अवसर पर 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक राजस्थान में ''वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान'' संचालित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास प्रारंभ किया है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जल संसाधनों की दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण प्रदेशों में गिना जाता है। देश के कुल भूभाग का लगभग 10 प्रतिशत और कृषि भूमि का 12.85 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, जबकि उपलब्ध सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत एवं भूजल मात्र 1.72 प्रतिशत ही उपलब्ध है।

राजस्थान की औसत वर्षा

राजस्थान की औसत वर्षा करीब 57.5 मिमी एवं पश्चिमी राजसथान की औसत वर्षा मात्र 3.27 मिमी ही है। कभी अल्प वर्षा तो कभी अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए संकट उत्पन्न करती हें। राज्य की बड़ी आबादी आज भी भूजल पर निर्भर है। लगातार बढ़ते दोहन के कारण अनेक जिलों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गया है। कई क्षेत्रों में पेयजल संकट का समाधान एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। खेती, उद्योग और शहरीकरण के विस्तार ने पानी की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में जल संरक्षण अब पर्यावरणीय चिंता के साथ आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता बन चुका है।

परंपरागत जल स्त्रोत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण को विकास की मूल धुरी मानते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों से बार–बार यह स्पश्ट किया है कि राजस्थान का भविष्य जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने परंपरागत जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन वर्षा जल संचयन, ग्रामीण जल संरचनाओं के विकास और पेयजल आपूर्ति की मजबूत बनाने की दिशा में कार्यों को गति प्रदान की है।

जलाशयों का गहरीकरण

राज्य सरकार ने जलदाय एवं ग्रामीण विकास विभागों के माध्यम से तालाबों, एनीकटों, नाड़ियों और जोहड़ों के संरक्षण एवं पुनर्भरण के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। अनेक जिलों में अमृत सरोवरों का निर्माण और पुराने जलाशयों का गहरीकरण कराया गया है।

मनरेगा के माध्यम से

मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण कार्यों को व्यापक स्तर पर जोड़ा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ–साथ जल संरचनाओं का विकास भी हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पेयजल योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा गर्मी के मौसम में पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई है।

वर्षा जल संग्रहण

राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों को भी गति देने का प्रयास किया है ताकि ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सके। साथ ही, वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों एवं संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सरंचनाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गंगा दशहरे से प्रारंभ ''वंदे गंगा जल संक्षण अभियान'' इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। अभियान के दौराव गांवों और शहरों में तालाबों, बावड़ियों, कुओं और जोहड़ों की सफाई, गहरीकरण और पुनर्जीवन के कार्य किए जाएंगे। वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

वृक्षारोपण और पर्यावरण

विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों को अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी न रहकर सामाजिक दायित्व बने। अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष वृक्षारोपण और

पर्यावरण संरक्षण भी रहेगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जल और जंगल का संबंध अत्यंत गहरा है।

पौधारोपण और चारागाह

जहां हरियाली बढ़ती है, वहां वर्षा जल का संरक्षण बेहतर होता है और भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया मजबूत होती है। इसलिए राज्य सरकार जल संरक्षण के साथ पौधारोपण और चारागाह विकास पर भी विशेष जोर दे रही है। राजस्थान की पारंपरिक जल संरचनाएं आज भी यह संदेश देती हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद दूरदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी से जल संकट पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

जल प्रबंधन क्षमता

जेसलमेर की कुण्ड प्रणाली, शेखावाटी की बावडियां और मेवाड़ के तालाब आज भी हमारे पूर्वजों की जल प्रबंधन क्षमता के जीवंत उदाहरण है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक जल संरचनाओं के संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में किए जा रहे प्रयास सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं।

जनजागरण अभियान

जल संरक्षण तभी सफल होगा जब समाज का प्रत्येक वर्ग इसे अपनी जिम्मेदारी माने। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को अपनाना होगा। फसलों के चयन में भी जल उपलब्धता का ध्यान रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में घर–घर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा। पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी जल संरक्षण को जनजागरण अभियान के रूप में चलाना होगा।

सकारात्मक परिणाम सामने आए

विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान जैसे राज्य में छोटे–छोटे स्थानीय जल स्त्रोतों का संरक्षण सबसे प्रभावी रणनीति हो सकती है। बड़े बांधों के साथ–साथ गांव स्तर पर तालाब, नाड़ी और जोहड़ विकसित करने से भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार संभव है। कई स्थानों पर सामुदायिक श्रमदान और सूखे जलाशयों को पुनर्जीवित करने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

नई दिशा देने का प्रयास

पंचायतों, धार्मिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भारतीय संस्कृति में जल को "अमृत" कहा गया है। यही भावना आज फिर जागृत करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा यह अभियान जल संरक्षण के प्रति सामाजिक चेतना को नई दिशा देने का प्रयास है।

व्यक्तिगत और सामाजिक संकल्प

यदि सरकार की योजनाओं के साथ जनभागीदारी मजबूती से जुड़ती हैं तो राजस्थान फिर एक बार जल प्रबंधन के आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है। गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर शुरू किया गया यह अभियान वास्तव में भविष्य को सुरक्षित करने का अभियान है। समय का स्पष्ट संदेश है, जल है तो कल है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण को व्यक्तिगत और सामाजिक संकल्प बनाना होगा। यही "वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान" की वास्तविक सफलता होगी।

<u>भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस, 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति, 577 प्रकरणों में जिम्मेदारी तय होगी</u>

भ्रष्ट–लापरवाह अफसरों पर एक्शन, 1 आरएएस समेत 20 बर्खास्त, 332 सस्पेंड, 17 की पेंशन रोकी

भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग, अनियमितता और लापरवाही जैसे मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल ने ढ़ाई साल में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है। एक आरएएस सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया है। 332 अधिकारियों और कार्मिकों को निलंबित किया है, जबकि 17 की पेंशन रोकी है। 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की है और 577 प्रकरणों में जांच कर जिम्मेदारी तय की जा रही है।

अखिल भारतीय सेवा के 9 प्रकरणों की जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में भजनलाल सरकार ने सख्त रूख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फाइलों को लंबित रखना, सरकारी धन का दुरूपयोग और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं होगी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सख्त संदेश है कि सरकारी सेवा जनसेवा के लिए है और जिम्मेदारी में लापरवाही और अनियमितता पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

हल्दीघाटी : स्वाभिमान, संघर्ष और अमर चेतना का युद्ध
महाराणा प्रताप के अदम्य साहस की ऐतिहासिक गाथा

—डॉ. भरत भूषण ओझा

भारतीय इतिहास में कुछ युद्ध केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़े गए, बल्कि वे राष्ट्र की आत्मा, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के प्रतीक बन गए। हल्दीघाटी का युद्ध भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक अध्याय है, जिसने यह सिद्ध किया कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस युद्ध के केंद्र में थे मेवाड़ के महान वीर शासक महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया।

मेवाड़ की धरती पर स्वतंत्रता का संकल्प : महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे भारतीय अस्मिता के प्रहरी थे। प्रताप ने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मेवाड़ की भूमि पर पराधीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। यही कारण था कि हल्दीघाटी का युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और साम्राज्यवादी विस्तार के बीच की टक्कर बन गया।

हल्दीघाटी : युद्धभूमि से अधिक एक भावना

18 जून 1576 को खमनोर की घाटी में यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। पीली मिट्टी के कारण यह क्षेत्र 'हल्दीघाटी' कहलाया। एक ओर महाराणा प्रताप की वीर सेना थी, तो दूसरी ओर मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां कर रहे थे। प्रताप की सेना संख्या और संसाधनों में कम होने के बावजूद उत्साह, रणनीति और देशभक्ति से भरपूर थी। उनके साथ झाला मान, हकीम खां सूरी और राजा रामशाह तोमर जैसे योद्धा थे, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए

प्रताप का पहला प्रहार और मुगल सेना में भय :

समकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूंनी ने अपनी पुस्तक मुन्तखाब– उत– तवारीख में लिखा है कि युद्ध के प्रारंभ में मेवाड़ की सेना ने इतना भीषण आक्रमण किया कि मुगल सेना कई मील पीछे हट गई। यह उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि युद्ध के शुरुआती चरण में प्रताप की रणनीति पूरी तरह सफल रही। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व चेतक पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरे। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि वीरता और निष्ठा का प्रतीक था। युद्ध के दौरान चेतक ने जिस प्रकार प्रताप की रक्षा की, वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया।

जनता की दृष्टि में विजेता : इतिहास केवल राजाओं की घोषणाओं से नहीं बनता, बल्कि जनता की भावनाएं भी उसका महत्वपूर्ण आधार होती हैं। कहा जाता है कि जब मुगल सेना विजय का नगाड़ा बजाते हुए लौट रही थी, तब मार्ग के गांवों के लोग उन पर हंस रहे थे और उनका उपहास कर रहे थे। यदि मुगलों की वास्तविक विजय हुई होती, तो जनता उनका सम्मान करती। यह घटना स्पष्ट संकेत देती है कि जनमानस ने महाराणा प्रताप को ही वास्तविक विजेता माना।

सीमित संसाधनों के बावजूद अडिग संघर्ष : इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप के पास लगभग पाँच हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना उनसे कई गुना अधिक विशाल थी। मुगलों के पास तोपें, बंदूकें और भारी सैन्य साधन थे, जबकि प्रताप की सेना मुख्यतः तलवार, भाले और साहस के बल पर लड़ रही थी। इसके बावजूद प्रताप ने कभी हार स्वीकार नहीं की। हल्दीघाटी के बाद भी उन्होंने अरावली की कठिन पहाड़ियों में रहकर संघर्ष जारी रखा और धीरे–धीरे मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को पुनः स्वतंत्र करा लिया। यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी।

युद्ध का परिणाम : पराजय नहीं, प्रतिरोध की विजय : कई इतिहासकार हल्दीघाटी के युद्ध को 'अनिर्णीत' मानते हैं, जबकि अनेक भारतीय विद्वान इसे महाराणा प्रताप की रणनीतिक विजय बताते हैं। यदि मुगलों को पूर्ण सफलता मिल गई होती, तो अकबर को बार–बार मेवाड़ पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराणा प्रताप ने जीवनभर मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही कभी अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। यही उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत थी।

प्रताप : भारतीय स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप का,जीवन त्याग, साहस और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शक्ति केवल संसाधनों में नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और राष्ट्रभक्ति में होती है। आज भी हल्दीघाटी का युद्ध भारतीयों को यह संदेश देता है कि सच्ची हार तब होती है जब व्यक्ति अपना स्वाभिमान खो देता है। प्रताप ने कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया, इसलिए वे भारतीय इतिहास में अमर नायक के रूप में स्मरण किए जाते हैं।

आज के भारत के लिए प्रेरणा : वर्तमान समय में जब इतिहास को नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास हो रहा

है, तब महाराणा प्रताप का संघर्ष और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका जीवन युवाओं को यह प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि आत्मबल और राष्ट्रप्रेम जीवित है तो कोई भी शक्ति व्यक्ति को झुका नहीं सकती। हल्दीघाटी केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान की वह ज्योति है, जो सदियों बाद भी राष्ट्र की चेतना को प्रकाशित कर रही है।

7.8 प्रतिशत से बढ़ी अर्थव्यवस्था, मार्च तिमाही में अनुमान से अधिक रही वृद्धि

2025–26 में 7.7 प्रतिशत की दर से हुआ इजाफा

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025–26 की जनवरी मार्च तिमाही में मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च के कारण अनुमान से अधिक 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। हालांकि इस अवधि के अंत में बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं ने आर्थिक परिदृश्य पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी।

पिछले वर्ष की समान तिमाही में जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत रही थी, जबकि अक्टूबर– दिसंबर तिमाही में यह आठ प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025–26 की समूची अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई, जो 2024–25 में 7.1 प्रतिशत बढ़ा, जो यह दर्शाता है कि वृद्धि केवल मांग पर आधारित नहीं थी, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी–मार्च तिमाही में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 7.9 प्रतिशत बढ़ा, जो यह दर्शाता है। कि वृद्धि केवल मांग पर आधारित नहीं थी, बल्कि उत्पादन में मजबूती भी रही। विनिर्माण, निर्माण, एवं सेवा क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन ने अर्थव्यवस्था की सहारा दिया। एनएसओ ने कहा कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी का आकार वित्त वर्ष 2025–26 में बढ़कर 323.12 लाख करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2024–25 के पहले संशोधित अनुमान 299.89 लाख करोड़ रूपये से अधिक है। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का आकार 2025–26 में 346.36 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2024–25 के 318.07 लाख की वृद्धि को दर्शाता है। यह 2022–23 को आधार वर्ष मानकर तैयार की गई नई श्रृखंला के तहत जारी जीडीपी आंकड़ों का दूसरा समूह है।

2027–28 में 7 प्रतिशत से ऊपर जा सकती है वृद्धि दर : नागेश्वरन– मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने इस पर कहा कि यदि वैश्विक परिस्थितियों बेहतर होती हैं तो वित्त वर्ष 2027–28 में भारत की वृद्धि दर फिर से सात प्रतिशत से ऊपर जा सकती है। उन्होंने कहा कि नीतिगत उपायों और आपूर्ति सुनिश्चित करने से अर्थव्यवस्था दोबारा तेज वृद्धि के रास्ते पर लौट सकती है।

आरबीआई ने रेपो दर को रखा बरकरार : आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक प्रमुख नीतिगत इदर रेपो को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा। साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊर्जा की ऊंची कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में समस्या के कारण वृद्धि और मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों के बीच विदेशी पूंजी आकर्षित करने और रूपए को समर्थन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। आरबीआई ने मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत ओर खुदरा मुद्रास्फिति के अनुमान को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है। पहले जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था। रिजर्व बैक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, मौजूदा आर्थिक परिवेश को देखते हुए एमपीसी ने आम सहमति ने नीतिगत दर को 5.25% पर बरकरार रखने का निर्णय किया है।

विदेशी पूंजी आकर्षिक करने के लिए प्रतिभूति पर कर छूट :–

सरकार ने रूपए पर दबाव को कम करने और विदेशी पूंजी आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों की ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दे दी है। सरकार ने पांच जून की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया। इसके तहत एक अप्रैल से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, विनियम या हस्तांतरण से होने वाली ब्याज आय एवं पूंजीगत लाभ कर छूट प्रदान की गई है। यह छूट विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इटरनेशनल सेटलमेंट्स पर लागू होगी। विदेशी निवेशकों को वर्तमान में 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए सूचीबद्ध शेयर और बॉन्ड पर 12.5 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होता है। इसके अलावा, सरकारी बॉन्ड से अर्जित ब्याज पर 20 प्रतिशत का 'विदहोल्डिंग टैक्स' भी देना पड़ता है। केंद्रीय बैंक ने पूर्ण पहुंच मार्ग के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के दायरे का विस्तार करते हुए 15, 30 और 40 वर्ष के नए सॉवरेन बॉन्ड इसमें शामिल किए हैं। आरबीआई ने सामान्य मार्ग के तहत निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अल्पकालिक निवेश, कोष रखने की सीमा और व्यक्तिगत प्रतिभूति सीमा से जुड़े प्रतिबंध भी हटा दिए हैं।

विकसित राजस्थान की मजबूत नींव

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में समग्र विकास का नया अध्याय

—कुलदीप धनखड़, विधायक विराटनगर

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प केवल आर्थिक प्रगति का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह समावेशी विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण पर आधारित एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि है। ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. के मंत्र को आधार बनाकर देश के विभिन्न राज्यों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इसी दृष्टि को धरातल पर उतारने का गंभीर और परिणामोन्मुख प्रयास दिखाई देता है। ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन, जल प्रबंधन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में राज्य सरकार की पहले विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम प्रशासन को सीधे गांवों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना है। शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने चली पहल के अंतर्गत प्रदेशभर में 2,839 ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए गए, जिनमे 13 विभागों ने भाग लेकर 48 से अधिक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई। इन शिविरों में 77 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार समस्याओं के समाधान को लेकर कितनी गंभीर है। प्रशासनिक जवाबदेही और जनसुनवाई की यह संस्कृति सुशासन की नई पहचान बन रही है। ग्राम विकास रथ अभियान ने सरकारी योजनाओं को गांव–ढाणी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक तकनीक से सुसन्जित रथों के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है तथा जनता के सुझाव सीधे सरकार तक पहुंच रहे हैं। यह पहल सरकार को जन–जन से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन गई है। राजस्थान दिवस पर प्रारंभमुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान राज्य के ग्रामीण विकास की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गांवों के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.14 लाख ग्रामीण आवास पूर्ण किए गए है, 2.19 लाख से अधिक आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं तथा जल जीवन मिशन के माध्यम से 14.64 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 1.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई सुविधाओं का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। कृषि और ग्रामीण समृद्धि के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है। किसान सम्मान निधि के तहत 76.18 लाख किसानों को 12,410 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6,565 करोड़ रुपये के दावे वितरित किए गए है तथा 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियां जारी की गई है। किसानों को 52,773 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है। बिजली बिलों में 53,130 करोड़ रुपये की सब्सिडी तथा 2.14 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार को चंदन वन योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उदयपुर, सिरोही, बांसकड़ा और प्रतापगढ़ में प्रस्तावित चंदन बनों के माध्यम से उच्च मूल्य वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 3,344 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत प्रत्येक वन में लगभग 11 हजार चंदन पौधे लगाए जाएंगे। यह पहल न केवल हरित आवरण बढ़ाएगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक आय और रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के संतुलन का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। जल सुरक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने ऐतिहासिक कदम उठाए है। रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इससे 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा तथा लगभग 2.82 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। दशकों पुरानी शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में यमुना जल साझेदारी योजना एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। हरियाणा से आवंटित यमुना जल के उपयोग हेतु दोनों राज्यों के बीच समझौता होने के बाद विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी पहल से सीकर, झुंझुनूं चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र के लाखों लोगों को दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा प्राप्त होगी। जल जीवन मिशन के तहत लाखों परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया है। जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और पेयजल उपलब्धता की ये पहल राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति को मजबूत बना रही है। ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान आज राष्ट्रीय नेतृत्व की स्थिति में पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सौर ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है तथा अक्षय ऊर्जा क्षमता में दूसरा स्थान रखता है। पिछले दो वर्षों में 8.670 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित की गई है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 65,412 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं तथा हजारों मेगावाट क्षमता की नई सौर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाखों परिवार स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। यह उपलब्धियां राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बना रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी राज्य सरकार, ने प्रभावी पहल की है। 11.58 लाख गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। लगभग 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी प्रशिक्षण से जोड़ा गया है तथा 16 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। हजारों महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रयास महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने के साथ–साथ उन्हें आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते हुए रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में 1.21 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं, जबकि 1.33 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। निजी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। 963 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 71 नए राजकीय महाविद्यालयों को स्थापना शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य को प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन विकासात्मक पहलों का सकारात्मक प्रभाव राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, खनन, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन सभी पहलों को समाहित करने वाला व्यापक दृष्टिकोण राज उन्नति के रूप में सामने आया है। यह विकसित राजस्थान की कार्ययोजना है, जिसमे कृषि, जल, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन के सभी आयाम शामिल है। राज उन्नति का मूल उद्देश्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शमां के नेतृत्व में राजस्थान विकास को ऐसी यात्रा पर अग्रसर है जिसमे गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा सभी विकास के सहभागी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत–2047 के संकल्प को साकार करने में राजस्थान की ये पहले महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सुशासन, जनभागीदारी और परिणामोन्मुख विकास को यह कार्यशैली राज्य को नई ऊंचाईयों की ओर ले जा रही है।

हिमाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव परिणाम 2026

क्र.	जिला परिषद	कुल वार्ड	भाजपा	कांग्रेस	अन्य	प्रमुख पार्टी
1.	ऊना	17	11	4	2	भाजपा
2.	कांगड़ा	54	22	12	20	निर्दलीय
3.	किन्नौर	10	9	1	0	भाजपा
4.	कुल्लू	14	9	4	1	भाजपा
5.	चंबा	18	6	6	6	टाई
6.	बिलासपुर	14	5	0	9	निर्दलीय
7.	मंडी	36	26	3	7	भाजपा
8.	लाहौल–स्पीति	10	3	5	2	कांग्रेस
9.	शिमला	25	10	9	6	भाजपा
10.	सिरमौर	17	11	3	3	भाजपा
11.	सोलन	17	10	5	2	भाजपा
12.	हमीरपुर	19	15	1	3	भाजपा
	कुल–	**251**	**137**	**53**	**61**	

मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए
भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री अजेय कुमार

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पधारने पर प्रदेश महामंत्री (संगठन) का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़ एवं राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवाड़ी

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण करते हुए
भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री अजेय कुमार

भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़

राज्यसभा सदस्य बने डॉ. सतीश पूनियां

राज्यसभा सदस्य बनी श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर

आर.एन.आई. पंजीयन क्र.-RAJHIN/2010/34673

मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

भाजपा प्रदेश कार्यालय में 'मन की बात' सुनते हुए
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़ एवं अन्य

दुर्गापुरा, जयपुर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को
सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोदी सरकार के 12 वर्ष की प्रदर्शनी का
उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
श्री मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री अजेय कुमार

भाजपा प्रदेश कार्यालय में वृक्षारोपण करते हुए
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़

ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. महेन्द्र कुमावत
पदभार ग्रहण करते हुए

शत्-शत् नमन

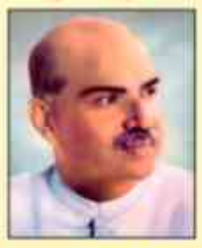

डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी
बलिदान दिवस (23 जून)

मरु कमल दर्पण (साप्ताहिक) प्रकाशन तिथि : 25 जून, 2026 प्रेषण तिथि : 29 जून, 2026

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक – डॉ. सतीश पूनियां द्वारा डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, 9, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, जौहरी बाजार,
जयपुर से मुद्रित एवं सी-51, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से प्रकाशित, सम्पादक – डॉ. सतीश पूनियां